

रजिस्टर्ड नं० एल० 33-एस० एम० 13-14/98.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 9 जनवरी, 1998/19 पौष, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 9 जनवरी, 1998

संख्या पी० सी० एच० एच० ए० (3) 3/96.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, निम्नलिखित नियमों के प्राख्य, जिन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) की धारा 186 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना प्रस्थापित करती हैं का इनसे सम्भवतः प्रभावित सर्वसाधारण या व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 186 की उप-धारा (5) द्वारा यथा अपेक्षित के अनुसार एन० द्वारा प्रकाशन किया जाता है। इन प्राख्य नियमों से सम्भाव्य प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति इन नियमों से सम्बन्धित कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता हो, तो वह उसे निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश, एन० डी० ए० काम्पलेक्स, ब्लॉक नं० 27, कसुम्पटी, शिमला-171009 को, इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर प्राप्त आक्षेप/सुझाव,

यदि कोई हों, पर, इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा, अर्थात् :—

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जिला योजना समिति (निर्वाचन) नियम, 1998 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) 'अध्यक्ष' से समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) 'समिति' से अधिनियम की धारा 185 के अधीन गठित जिला योजना समिति अभिप्रेत है;

(घ) 'सदस्य' से समिति का सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) पद और अभिव्यक्तियाँ जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. जिला योजना समिति (अधिनियम की धारा 185).—(1) अधिनियम की धारा 90 के अधीन जिला परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् राज्य सरकार, धारा 185 की उप धारा (2) के खण्ड (घ) में यथा अपेक्षित के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा जिला निर्वाचन समिति के सदस्यों की कुल संख्या और प्रत्येक जिला योजना समिति के लिए निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या का, जिले के लिए ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात में, अवधारण करेगी।

(2) जैसे ही उप नियम (1) के अधीन आदेश जारी कर दिया जाता है, उपायुक्त जिला में, जिला परिषद और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों की, उनमें से, ऐसे सदस्य (सदस्यों) जैसे कि सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, को निर्वाचित करने के लिये, बैठक बुलायेगा।

(3) निर्वाचन, गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा और नवीं की वरावरी की दशा में परिणाम का विनिश्चय लाट द्वारा किया जाएगा।

4. जिला योजना समिति का अध्यक्ष (चेयरपर्सन).—(1) नियम 3 के अधीन समिति के सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात् और उक्त निर्वाचन की सात दिन की अवधि के भीतर, उपायुक्त अधिनियम की धारा 185 की उप धारा (2) में निर्दिष्ट जिला योजना समिति के सभी सदस्यों की, अपनी अध्यक्षता के अधीन समिति के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) का निर्वाचन करने के लिए बैठक बुलाएगा।

(2) ऐसी बैठक की गणपूर्ति, अधिनियम की धारा 185 की उप धारा (2) में निर्दिष्ट सदस्यों के दो-तिहाई से होगी।

(3) निर्वाचन, गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा और मतों की वसूली की दशा में परिणाम का निनिश्चय लाट द्वारा किया जाएगा।

(4) बैठक की कार्यवाही, समिति के सचिव द्वारा, जिला योजना समिति के रजिस्टर में अभिलिखित की जायेगी।

(5) कोई भी सदस्य अध्यक्ष (चेयरपर्सन) को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे सकेगा और अध्यक्ष (चेयरपर्सन) भी, निदेशक पंचायती राज को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना त्याग-पत्र दे सकेगा।

यदि अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य जिला परिषद का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य या नगरपालिका का महापौर/अध्यक्ष या सदस्य, लोक सभा का सदस्य, यथास्थिति नहीं रह जाता है तो वह स्वतः ही नमिति का अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या सदस्य नहीं रहेगा।

परन्तु यह कि ऐसी सभी रिक्रिया उपायुक्त द्वारा नियम 3 में यथा अधिकथित रीति में उपायुक्त द्वारा 3 (तीन) मास के अवधि की भीतर भरी जायेगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

वित्तायुक्त एवं सचिव।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. PCH-HA(3)3/96, dated, 9-1-1998 as required under Article 348 (3) of Constitution of India].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 9th January, 1998

No. PCH-HA(3)3/96.—The following draft of the rules which the Governor of Himachal Pradesh proposes to make in exercise of powers conferred by sub section (1) of section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), is hereby published as required by section (5) of section 186 of the said Act for the information of the general public or persons likely to be affected thereby. If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection or suggestion to make with regard to the said rules, he may send the same in writing within 30 days from the date of its publication in the Rajptra to the Director, Panchayati Raj, Himachal Pradesh, SDA Complex, Block No. 27, Kasumpti, Shimla-171009. The objections/suggestions, if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government before finalising these rules, namely:—

DRAFT RULES

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh District Planning Committee (Election) Rules, 1998.

(2) These rules shall come into force at once.

2. *Definitions.*—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4

- (b) "Chairman" means the Chairman of the Committee;
- (c) "Committee" means the District Planning Committee constituted under section 185 of the Act;
- (d) "Member" means the member of the committee;
- (e) "Section" means section of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules, but not defined, shall have the same meaning as has been assigned to them in the Act.

3. *District Planning Committee (Section 185 of the Act).*—(1) Immediately after the election of the Chairman of the Zila Parishad under section 90 of the Act, the State Government shall determine, by an order, published in the Official Gazette, the total number of members of each District Planning Committee and the number of members to be elected to each District Planning Committee as required under clause(d) of sub-section (2) of section 185 in ratio of the rural and urban population for the District.

(2) As soon as the order is issued under sub rule (1), the Deputy Commissioner shall convene the meeting of the elected members of the Zila Parishad and the Municipalities in the District of elect from amongst themselves such member(s) as determined by the Government.

(3) The election, shall be by secret ballot and in case of equality of votes, the result shall be decided by draw of lots.

4. *Chairperson of the District Planning Committee.*—(1) After the election of the members of the Committee under rule 3, and within a period of seven days of the said election, the Deputy Commissioner shall convene the meeting of all the members of the District Planning Committee referred to in sub section (2) of section 185 of the Act under his Chairmanship for the election of Chairperson of the Committee.

(2) The quorum of such meeting shall be two-third of the members referred to in sub-section (2) of section 185 of the Act.

(3) The election, shall be by secret ballot and in case of equality of votes the result shall be declared by the draw of lots.

(4) Proceedings of the meeting shall be recorded in the proceeding register of the District Planning Committee by the Secretary of the Committee.

(5) Any member may resign from his membership by writing under his hand addressed to the Chairperson and the Chairperson may also tender his resignation by writing under his hand addressed to the Director of Panchayati Raj.

(6) In case, the Chairperson or member ceases to be the Chairperson or member of Zila Parishad or Mayor/President or Member of Municipality, member of the house of the people, as the case may be, he shall automatically cease to be a Chairperson or member of the Committee:

Provided that all such vacancies shall be filled by the Deputy Commissioner within a period of three months in the manner as laid down under rule 3.

By order,

Sd/-

F. C.-cum-Secretary.